

श्रसाधा रण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--- उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

म० 215]

मई विल्लो, शनिवार, न अम्बर, 30, 1968/श्रग्रहायरा 9, 1890

No. 215] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 30, 1968/AGRAHAYANA 9, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्यावी जाती है जिससे कि ्रैयह ब्रलग संकलन के रूप में रखाजा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFIC ATIONS

New Delhi, the 28th November 1968

G.S R 2098.—The following Order made by the President is published for general nformation:--

Order

In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 51 of the States Reorganisation Act. 1956 (37 of 1956), I, Zakir Husain, President of India, after consultation with the Governor of Madhya Pradesh and the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby establish a permanent Beach of the Madhya Pradesh High Court at Indiae and further direct that such Judges of the High Court of Madhya Pradesh, being not less than four in number, as the Chief Justice may from time to time nominate, shall at Indore in order to exercise the jurisdiction and power for the time being vested in that High Court in respect of cases arising in the revenue districts of Indore, Ujiain, Dewas, Dhar, Jhabua, Ratlam, Mandsaur West Nimar (Khargone), Shajapur and Rajgarh:

Provided that the Chief Justice may, for special reasons, order that any case or class of cases arising in any such district shall be heard at Jabahnur

[No F 16/20/68-Judl.III(i).]

G.S.R. 2099.—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), I, Zakir Husain, President of India, after consultation with the Governor of Madhya Pradesh and the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby establish a permanent Bench of the Madhya Pradesh High Court at Gwalior and further direct that such Judges of the High Court of Madhya Pradesh being not less than two in number, as the Chief Justice may from time to time nominate, shall at Gwalior in order to exercise the jurisdiction and power for the time being vested in that High Court in respect of cases arising in the revenue districts of Gwalior, Shivperi, Datia, Guna, Vidisha (Bhilsa). Bhind and Morena:

Provided that the Chief Justice may, for special reasons, order that any case or class of cases arising in any such district shall be heard at Jabalpur.

New Delhi, November 18, 1968. ZAKIR HUSAIN, Prosident.

J. M. LALVANI, Jt. Socy.

[No. F.16/20/68-Judl.III(ii).]

पृष्ठ **वंद्यानव** प्रक्षिसूचनाएं

नई दिल्ली 28 नवम्बर, 1968

ची॰ एस॰ चार॰ 2100.---राष्ट्रपति द्वारा किया गया विस्वविधित वायेच वर्षे साधारण की जानकारी के सिए प्रकाशित किया जाता है:---

सायेस स

राज्य पुर्गनठन सिंधिनियम, 1956 (1956 का 37) की बारा 51 की उपधारा (2) द्वारा प्रवैत्त सिन्तयों का प्रयोग करते हुए मैं, खाकिर हुसैन, भारत का राष्ट्रपति, भध्य प्रवेश के राज्यपाल और मध्य प्रवेश के जन्म न्यायालय के मुख्य-न्यायमूर्ति से परामम करने के पश्चात, मध्य प्रवेश जन्म न्यायालय की एक स्थायी न्यायपी उप्तद्वारा इन्दौर में स्थापित करता हूं भीर यह निदेश की देता हूं कि मध्य प्रवेश के उच्च न्यायालय के बार से धन्यून ऐसे न्यायाधीक, जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति समय समय पर नाम निर्दिष्ट करें, इन्दौर उज्जैन, देवास, धार, अभुआ, रतलाम, मन्दसौर, पश्चिमी निमार (बाराना) शाजापुर और राजार के राजस्व जिलों में उद्भूत होने वाले मामलों के बार में उस जिल्च न्यायालय में तत्समय निहित मिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के लिए इन्दौर में बैठेंगे:

परन्तु मुख्य न्यायमूर्ति, विभिन्द कारणों से, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी जिले में उद्मूत होने वाला कोई मामला या मामलों का वर्ग जवलपुर में सुना जाएगा।

[सं॰ फा॰ 16 / 20 / 68 —वा॰ III (i)]

जी एस० ग्राप्ट० 2101.—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित ग्रादिश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

श्रादेश

राज्य पुनर्गठन श्रधिनियम, 1956 (1956 का 37) की खारा 51 की उपधारा (2) द्वारा प्रदक्ष मनितयों का प्रयोग कर ते हुए मैं, जाकिर हुसैन, भारत का राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीट एतद्वारा ग्वालियर में स्थापित करता हूं और यह निदेश भी बेसा हूं कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के दो से श्रम्यून ऐसे न्यायाधीश जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति समध समय पर नाम मिविष्ट करे, ग्वालियर, शिवपुरी, दितया, गुना, विविशा (भैलसा), भिड और मोरेमा के राजस्व जिलों में उद्भूत होने वाले मामलों के बारे में उस उच्च न्यायालय में तस्समय निहित्त श्रिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्वालियर में बैठेंगे।

परन्तु मुख्य न्यायमूर्ति , विशिष्ट भारणों से, यह नियेश दे सकेगा कि ऐसे किसी असे में उद्भृत होने बाला कोई नामसा या सामलों का वर्ग जबलपुर में सुना जाएगा ।

नई विल्ली, 18 नवस्वर, 1968 काकिर **हुसै**न, राष्ट्रपत्ति

[सं• फा॰ 16 / 26 / 68-न्या॰ III (II)]

अ ॰ स ॰ आख्रवाणी, संयुक्त समित्र।